एक अच्छी किताब रोशनी का नया दरवाजा खोलती है।
– अज्ञात

कोल सेक्टर में भयानक ठहराव

41 कोल ब्लॉक में कमर्शल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहले ही की गई घोषणाओं में यह फैसला भी शामिल था।

आरती जोशी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 41 कोल ब्लॉक में कमर्शल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहले ही की गई घोषणाओं में यह फैसला भी शामिल था। याद रहे, पिछले कुछ सालों में कोल सेक्टर भयानक ठहराव से गुजरा है।

1993 से 2010 के बीच हुई कुल 218 नीलामियों में सिर्फ 4 को छोड़कर बाकी सभी 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थीं। इसके छह साल बाद नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने पुराने मामलों में उलझने के बजाय इस बात पर हैरत जताई कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश क्यों है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कोयले का खनन और खपत बढ़ाने की राह में मौजूद सारी मुश्किलें दूर करने का मन बना चुकी है। इधर काफी समय से इस क्षेत्र में संभावनाएं कम ही होती दिखी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया में पर्यावरण के सवाल पर बढ़ती जागरूकता के चलते कोल माइंस और थर्मल पावर प्लांट्स के खिलाफ बने माहौल की है।

विश्व बैंक 2015 में ही ऐसी इकाइयों को फंड न देने का ऐलान कर चुका है। एक दिक्कत भारतीय कोयले की क्वॉलिटी से भी जुड़ी है जिसमें राख ज्यादा निकलती है और जिसकी प्रति इकाई ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम है। तीसरी बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के ज्यादातर कोयला भंडार घने जंगलों या आबादी वाले इलाकों में हैं, जिससे खनन शुरू होने के पहले ही परियोजना विवादग्रस्त हो जाती है।

प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सुधार लागू करने और स्थानीय आबादी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने की बात कही है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कार्ययोजना तैयार की है। कोल सेक्टर को लेकर पिछले दिनों उठे विवादों को एक तरफ रख दें तो यह बात भी ध्यान रखने की है कि कई कंपनियों ने कोल ब्लॉक खरीदने के कई साल गुजर जाने के बाद भी माइनिंग शुरू नहीं की थी। इसके पीछे उनका दूसरी परियोजनाओं में व्यस्त होना भी एक कारण हो सकता है लेकिन धंधे में पर्याप्त मुनाफे की उम्मीद न होना इसकी बड़ी वजह बताई जाती रही है। बहरहाल, यह सबके हित में है कि कोल सेक्टर के पुनरुद्धार की जितनी भी संभावना हो उसे आगे बढ़ाया जाए।

अगर देश कोयले के उत्पादन के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी कामयाब होता है, साथ ही पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है तो न सिर्फ आत्मनिर्भरता की दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को इससे उम्मीद की वह रोशनी भी मिलेगी, जिसकी उसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है।

मस्तिष्क को भ्रान्ति

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। वह पीठासीन देवी देवताओं और बुद्धाओं को पेय प्रस्तुत करते हैं। वह नशों के प्रभावों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वह शरीर के द्वारा आसानी से पच सके और मस्तिष्क को भ्रान्ति न दे। योग को अब वैश्विक मान्यता मिल गई है। कोरोना संक्रमण काल में भी योग हमारे लिए संजीवनी साबित हो रहा है। हम योग को अपना कर इस महामारी में भी अपने स्वस्थ रख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि 'योगः कर्मसु कौशलम' यानी हमारे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ योग है। योग यज्ञ है और यज्ञ कर्म है। योग जीवात्मा और परमेश्वर के मिलन का साधन मात्र ही नहीं बल्कि ईश साधना का भी साध्य भी है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने योग को सर्वोपरि बताया है। 'योगस्थः कुरु कर्माणि' इसका तात्पर्य है कि योग में स्थिर होकर ही सद्चित कर्म संभव है।

संपादकीय

एकता और अखण्डता

23 जून को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्वतंत्र भारत में भी देश की एकता और अखण्डता के लिये बलिदान देना होगा, लेकिन ऐसा हुआ। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की एकात्मता के लिये सर्वोच्च बलिदान दिया।

कोई भी बलिदान तभी सार्थक होता है जब वह उस उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ होता है जिसके लिये वह बलिदान दिया गया। डॉ. मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर राज्य में, और इसके निमित्त से पूरे देश में "एक प्रधान, एक विधान और एक निशान" को स्थापित करने के संकल्प के साथ किया गया था। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद राज्य से सदरे रियासत और वजीरे आजम के पदनाम हटा कर क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदनाम प्रस्थापित कर दिये गये। इस प्रकार एक प्रधान की बात लागू हो गयी। किन्तु राज्य का अलग संविधान और अलग राजकीय ध्वज अलगाव को बढ़ाता ही गया। इसके कारण जो प्रश्न खड़े हुए वे इस देश के मानस में लगभग सात दशकों तक गूँजते रहे, अपना उत्तर खोजते रहे। इन प्रश्नों को उत्तर मिला 5 अगस्त 2019 को जब केन्द्र की सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन कर भारत का संविधान जम्मू कश्मीर राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया। अब वहाँ न अलग संविधान है और न अलग झंडा। पश्चिमी पाक और पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों, गोरखों, वाल्मीकियों, राज्य की महिलाओं को तीन पीढ़ियों तक अन्याय सहने के बाद अब वे अधिकार हासिल हुए हैं जिन्हें भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक के लिये सुनिश्चित करता है।

चीन को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत दिन–ब–दिन अमेरिका का खासमखास बनता जा रहा है और उसकी महत्वाकांक्षाओं की राह में बहुत बड़ी बाधा है।

सीमा का निर्धारण

जनरल एन सी विज।

भारत और चीन के आपसी रिश्ते वर्ष 1962 में चीन द्वारा अकारण किए गए हमले के बाद से ही कभी सहज नहीं रहे। वैसे तो उस समय सीमा संबंधी मुद्दा ही समस्या का मूल कारण था, लेकिन विगत वर्षों में कई और भी मुद्दे इसमें जुड़ गए हैं। दरअसल, वर्तमान समय के चीन ने दुनिया की नंबर वन ताकत बनने का मंसूबा पाल रखा है और इसी वजह से वह अमेरिका के साथ भी कटुतापूर्ण आर्थिक टकराव और शक्ति संघर्ष से बाज नहीं आ रहा है। चीन को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत दिन–ब–दिन अमेरिका का खासमखास बनता जा रहा है और उसकी महत्वाकांक्षाओं की राह में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए भारत को नीचा दिखाकर उसका मनोबल गिराना उसे जरूरी लगता है।

अब तक सीमा का निर्धारण नहीं होना, इस समस्या के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। शांति का आधार चूंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) ही है, इसलिए जब तक इस रेखा के वास्तविक स्थान के बारे में कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक शांति कायम होने के आसार ना के बराबर हैं। नक्शे पर इस रेखा को दर्शाने और जमीन पर इसका परिसीमन करने के लिए संयुक्त कार्य समूह जैसी विभिन्न व्यवस्थाएं

की गईं और 'विशेष प्रतिनिधियों' की बैठकें भी आयोजित की गईं। यहां तक कि इसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए मानचित्रों का भी आदान–प्रदान किया जाना था। केंद्रीय क्षेत्र (सेंट्रल सेक्टर) के लिए मानचित्रों का आदान–प्रदान वर्ष 2002 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद यह प्रकिया बंद हो गई क्योंकि सब कुछ चीन के दीर्घकालिक नापाक मंसूबों के अनुरूप नहीं हो रहा था। यह चीन की चिर–परिचित कुटिल चालबाजी को दर्शाता है।

हाल में लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ जैसे कई मामले इन वजहों से होते दिख रहे हैं। एलएसी पर स्पष्टता की कमी से उन्हें एक बहाना मिल गया है। वास्तव में दोनों एक–दूसरे की मान्यताओं को अच्छी तरह समझते हैं। समय के साथ वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि विवाद के 23 ऐसे क्षेत्र (लद्दाख में 11) हैं, जिनके समाधान की जरूरत है। गलवान घाटी इनमें शामिल नहीं है। हाल में गलवान में हुई घटना से इस क्षेत्र में चीन की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाएं सामने आ गई हैं। चीन के विदेश मंत्री ने अब दावा किया है कि गलवान घाटी हमेशा से उनकी रही है, जिससे जाहिर होता है कि चीन की नजर काफी दूर तक है। डीबीओ–काराकोरम दर्रे पर कब्जे की कोशिश तथा उसे शक्सगम घाटी (भारतीय क्षेत्र, जो पाकिस्तान द्वारा उसे सौंपा जा चुका है) से जोड़ना और फिर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने में पाकिस्तान की सहायता करना उसकी दीर्घकालिक रणनीति है। उत्तर पूर्वी लद्दाख पर कब्जे से चीन को अक्साई चिन मार्ग तक मजबूत पहुंच और चीन–पाक आर्थिक गलियारे को सुरक्षा मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस बड़े खतरे के बारे में बताने के लिए 19 जून, 2020 को सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने संबोधन में आठ बिंदुओं को सामने रखा। इनमें सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास, सैन्य बलों को बेहतर साजो सामान की उपलब्धता और तैयारियां, सीमावर्ती इलाकों में निरंतर पैट्रोलिंग और मजबूत प्रतिक्रिया देने की क्षमता शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने एलएसी, विशेष रूप से गलवान घाटी की स्थिति पर भी प्रकाश डाला।

सूडोकु नवताल-5391

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

Jagrutidaan.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5390 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अपना ब्लॉग

शांति में दिलचस्पी

मोहन। भारत को इस स्थिति का सामना राजनयिक, आर्थिक और सैन्य, सभी धरातलों पर करना होगा। आखिरी बात यह कि जब चीनी ऐसे आक्रामक तौर–तरीके दिखाते हैं तो भारत को उनकी संवेदनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? तिब्बत, हांगकांग, दक्षिण चीन सागर आदि जैसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके लिए चीन दुनिया के प्रति जवाबदेह है। भारत को धीरे–धीरे आर्थिक पहलुओं पर भी चीन से अलग होना शुरू करना पड़ेगा। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का गुस्सा भारतीय लोगों में पहले ही पैदा हो रहा है। अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया है, तो मामले को यहीं विराम देने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह देश के हित में होगा कि हम अपने सामने आने वाले खतरे पर ध्यान दें और इस पर अभी राजनीति न करें। पीएम ने पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है कि 'भारतीय क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करने का हमारा संकल्प है और अगर उकसाया गया तो निर्णायक जवाब देने में भी हम सक्षम हैं'।